संख्या: 02/2020/46/तीस-1-2020-5(1)/2017

प्रेषक,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक, 03 फरवरी, 2020

विषय: क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-908बी/डीए/पूर्व/19-75जेईटी/वि0/17-18, दिनांक 15.10.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-32/2017/1174(1)/तीस-1-2017-5(1)/2017, दिनांक 22.12.2017 द्वारा क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर के निर्माण हेतु आंकलित लागत रू0 804.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2017-18 में कतिपय शर्तो के अधीन प्रथम किश्त के रूप में रू0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की गयी है। क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 15.10.2019 द्वारा क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर के निर्माण हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू0 404.50 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त क्षेत्रीय कार्यशाला, गोरखपुर के निर्माण हेतु स्वीकृत कुल लागत रू0 804.50 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में रू0 404.50 लाख (रूपये चार करोड़ चार लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि :-

(1) योजना की अनुमोदित लागत में ही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद्धि होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने स्रोतों से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

(2) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(3) भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराते हुये समयबद्ध रूप से कार्य पूर्ण कराया जाय। इसका दायित्व कार्यदायी संस्था एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा। साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा, कराये जा रहे कार्यों की वर्तमान में तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में दिये गये निर्देशों तथा इस संबंध में स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर दिये गये निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त व्यय के संबंध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

कराने का उत्तरादायित्व उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा। ऋण स्वीकृति के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के संगत शासनादेशों की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्धता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम तथा उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम का होगा।

(7) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जायेगा। योजना की गाईड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अन्य समस्त शर्ते पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-32/2017/1174(1)/तीस-1-2017-5(1)/2017, दिनांक 22.12.2017 के अनुरूप यथावत रहेंगी ।

(9) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा। उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो। उक्त के अतिरिक्त कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित समय में तथा उत्कृष्ट श्रेणी की गुणवत्ता के साथ कार्य को पूर्ण कराये जाने तथा किसी भी दशा में कार्यो की लागत में कोई पुनरीक्षत न किये जाने के संबंध में अनुबन्ध अनिवार्य रूप से निष्पादित करा लिये जायें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा ।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या-ई-9/1696/दस-2019, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या: 02 /2020/46(1)/तीस-1-2020-5(1)/2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 ।
6. वित्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
8. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3 ।
11. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
12. गाई फाइल ।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in